

“हमें कुछ मुफ्त राशन मिलता है—5 किलो चावल या 5 किलो आटा प्रति सिर। बस इतना ही। हमें कोई मदद या कोई अन्य प्रावधान नहीं मिलता है।” झारखंड के हज़ारीबाग की एक प्रवासी कार्यकर्ता रौनक परवीन का यह कहना है उनके परिवार को पिछले साल जून से मिल रही सहायता के बारे में।

रौनक उन प्रवासी कामगारों में से हैं जो 2020 के लॉकडाउन के दौरान अपने गाँवों लौटने के लिए मजबूर हो गए थे और बाद में कोविड-19 महामारी के चलते नौकरी के नुकसान से प्रभावित थें। रौनक के परिवार के पास उनके राशन कार्ड थें, पर उन्होंने देखा कि बहुत सी महिलाओं के पास राशन कार्ड नहीं थें और इसलिए वे राशन सहायता प्राप्त करने में असमर्थ थीं।

रौनक ने यह भी देखा कि कई महिलाएँ बेरोज़गार थीं। आजीविका के कोई अवसर न होने के कारण वे अपना जीवन यापन करने और अपना घर चलाने के लिए संघर्ष कर रही थीं। रोज़गार का एकमात्र प्रमुख स्रोत मौसमी खेतिहर मज़दूर के रूप में काम करना था—एक ऐसी नौकरी जहाँ असफल फसल या प्राकृतिक आपदा का मतलब हो सकता है कोई काम न होना। यह इसके बावजूद कि रौनक सहित कुछ महिलाएँ शिक्षित हैं और शिक्षक के रूप में काम करने में समर्थ हैं।

यह अनिश्चितता महामारी में और बढ़ गई, इसलिए गाँव की महिलाएँ सुरक्षित आय के स्रोतों पर ज़ोर दे रही हैं। रौनक ने अपने गाँव की अन्य महिलाओं के साथ एक अनौपचारिक बचत समूह शुरू करने का फैसला किया। समूह के लगभग 150 सदस्य प्रत्येक रविवार को मिलते हैं, और हर सप्ताह अपने सामूहिक बचत बॉक्स में 100 रुपये जोड़ते हैं। यह राशि सदस्यों के किसी भी समय उधार लेने के लिए उपलब्ध है। अधिकतम निकासी सीमा है 5,200 रुपये क्योंकि प्रत्येक सदस्य ज़्यादा से ज़्यादा एक वर्ष में इतनी ही राशि की बचत करने में सक्षम होगा। पिछले कुछ महीनों में बचत राशि को घटाकर 10 रुपये प्रति व्यक्ति कर दिया गया है। रोज़गार के अवसरों की कमी और कुछ मामलों में मानसून की शुरुआत के चलते काम के नुकसान के कारण महिलाएँ उतनी बचत नहीं कर पाई हैं।

रौनक एक औपचारिक स्व-सहायता समूह बनाने और स्थापित करने के लिए भी काम कर रही हैं जो सरकारी लाभ और योजनाओं के लिए योग्य होगा। तब तक यह बचत समूह अपने सदस्यों को उनकी तात्कालिक जरूरतों, जैसे कि परिवार के स्वास्थ्य और त्योहार के खर्च, को पूरा करने की अनुमति दे रहा है और साथ ही उन्हें सामूहिकता की शक्ति के बारे में भी सिखा रहा है।